''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'', अभियान से सामाजिक परिवर्तन आया- भजनलाल

मुख्यमंत्री ईवी बस में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के लिए ठिकरिया गाँव पहुँचे

जयपुर, 16 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान, मजदूर, महिला और युवाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके सशक्त बनने से देश और प्रदेश विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने माता-बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई हैं।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम चौपाल में कहा कि अनावश्यक ईंधन खर्च से बचना चाहिए साझा वाहन उपयोग की आदत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि ईंधन की बचत आर्थिक बचत से जुड़ी हुई है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बगरू के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री शनिवार को बगरू के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही सामाजिक परिवर्तन आया। घर-घर शौचालय निर्माण से महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा मिली। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर तथा हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य किया। जन-धन योजना के माध्यम से बैंक खाते खुलवाकर योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बगरू के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री निवास से इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) बस से पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विभागों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यात्रा की।

उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन बचत के आव्हान पर ग्राम-2026 के आयोजन को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक ईंधन खर्च से बचना चाहिए और साझा वाहन उपयोग की आदत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि ईंधन की बचत आर्थिक बचत से भी जुड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि हमने राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके तहत हुए एमओयू धरातल पर तेजी से उतर रहे हैं, तथा युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथ ही, स्वरोजगार के लिए हम युवाओं को ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं।

मुख्यमंत्री से राजीविका की लाभार्थी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किये। इंद्रा शर्मा ने कहा कि राजीविका की मदद से हम घर और गांव से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से सक्षम बनी हैं। हमारे समूहों की महिलाएं सैनेटरी नैपकिन, बगरू प्रिंट, अन्नपूर्णा रसोई और बर्तन बैंक क्षेत्र में काम कर रही हैं। मेरी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है, जिससे मैं अब मिलेनियर दीदी बन गई हूं। कोमल शर्मा ने कहा कि मैं वेस्ट सामग्री को रिसाइकिल कर पेपर बनाने का कार्य करती हूं। हमारे गांव में 13 एसएचजी हैं। राजीविका की मदद से हम पेपर प्रोडक्ट बनाने का कार्य कर पा रहे हैं। हम सालाना 10 से 12 लाख रुपये का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें से 5-6 लाख रुपये की बचत हमें हो रही है। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

केन्द्र सरकार ने एनटीए में नए अधिकारी लगाये

नई दिल्ली, 16 मई। नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर बढ़ ते विवाद के बीच केन्द्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियां की हैं। एनटीए में चार बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

- **नीट पेपर लीक पर सरकार का एक्शन।**

सरकार ने एजेंसी में दो नए संयुक्त सचिव और दो संयुक्त निदेशक नियुक्त किए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) की 1998 बैच की अधिकारी अनुजा बापट और भारतीय राजस्व सेवा (कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्स) की 2004 बैच की अधिकारी रुचिता विज को एनटीए में संयुक्त सचिव नियुक्त किया , गया है।

दोनों की नियुक्ति पांच साल के लिए की गई है। इसके अलावा, भारतीय राजस्व सेवा (इनकम टैक्स) के अधिकारी आकाश जैन और भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा के अधिकारी आदित्य राजेन्द्र भोजगढि या को संयुक्त निदेशक बनाया गया है।

अमेरिका ने ईरान पर हमले का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 तैयार किया

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया

वॉशिंगटन, 16 मई। अमेरिकी सेना कथित तौर पर एक बार फिर ईरान पर हमलों की योजना बना रही है। ईरान के साथ शांति वार्ता के किसी नतीजे पर न पहुंचने के बाद अमेरिका को लग रहा है कि सैन्य हमले ही तेहरान पर दबाव बना सकते हैं। अमेरिका और इज़रायल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई। 8 अप्रैल को अस्थायी सीज़फायर के बाद दोनों पक्षों की बातचीत के जरिए समझौते पर पहुंचने की कोशिश अभी तक नाकाम रही है। इससे फिर लड़ाई शुरू होने की आशंका ने जोर पकड़ा है।

- **अखबार ने कहा कि अमेरिका व इज़रायल ईरान के खिलाफ नए सिरे से भीषण हमले करने की तैयारी में जुटे हैं।**

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू करने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की योजना तैयार की है। सैन्य समाधान का यह प्लान तब बना है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन का अपना दो दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि पेंटागन आने वाले दिनों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की योजना बना रहा है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस सप्ताह कांग्रेस के समक्ष गवाही देते हुए सांसदों से कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो हमारे पास स्थिति को आगे बढ़ ाने, यानी हमले तेज करने की योजना मौजूद है।

पश्चिम एशिया के दो अधिकारियों ने अखबार को बताया कि अमेरिका और इज़रायल के अधिकारी ईरान के खिलाफ हमलों को अगले सप्ताह फिर से शुरू करने की गहन तैयारियों में जुटे हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप फिर हमले शुरू करने का फैसला करते हैं तो ईरान के बुनियादी ढ ांचे को निशाना बनाया जा सकता है।

रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की योजना मेंतीन विकल्प हैं। इसमें पहला ईरान के सैन्य और बुनियादे ढ ांचे पर हवाई हमलों का है। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान की जमीन पर विशेष अभियान के लिए सेना उतारी जाए, ताकि वे जमीन के काफी नीचे गहराई में दबे हुए परमाणु सामग्री के भंडारों को खत्म कर सकें। प्लान का तीसरा विकल्प यह है कि अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप पर कब्जा करे। खर्ग ईरानी तेल निर्यात का एक बड़ा केंद्र है। इसमें मुश्किल यह है कि खर्ग पर कब्जा बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। ईरान को यहां की परिस्थिति से मिलने वाला फायदा अमेरिका की मुश्किल बढ़ाएगा।

नीदरलैंड चोल ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाएगा

ये पट्टिकाएं 300 वर्षों से नीदरलैंड के लीडन विश्वविद्यालय में रखी हुई हैं

नई दिल्ली, 16 मई । नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय ने करीब 300 वर्षों से अधिक समय से अपने पास सुरक्षित रखी गईं 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपट्टिकाओं को शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में भारत को लौटाने का ऐलान किया।

- **विश्वविद्यालय ने ऐलान किया कि प्र.मंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एक औपचारिक समारोह में इन पट्टिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा और बाद में किसी अन्य अवसर पर भारत को लौटा दिया जाएगा।**

विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में कहा कि शनिवार को हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित औपचारिक समारोह में इन चोल ताम्रपट्टिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद किसी अन्य अवसर पर इन्हें आधिकारिक रूप से भारत को हस्तांतरित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने अपने लेख में कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने चोल ताम्रपट्टिकाओं को भारत लौटाने का निर्णय लिया है। यह फैसला नीदरलैंड की राष्ट्रीय 'औपनिवेशिक संग्रह समिति' की सिफारिश के बाद लिया गया। समिति ने अपनी जांच में पाया कि ये ऐतिहासिक वस्तुएं औपनिवेशिक काल के दौरान दक्षिण भारत से, बिना वास्तविक अधिकारधारकों की सहमति के, बाहर ले जाई गई थीं।

विश्वविद्यालय के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2023 की गर्मियों में चोल ताम्रपट्टिकाओं को वापस करने का अनुरोध किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने स्वतंत्र विशेषज्ञों से इनकी उत्पत्ति और स्वामित्व संबंधी जांच कराई। साथ ही मामले को औपनिवेशिक संग्रह समिति के पास भेजा गया, जिसने अतिरिक्त अध्ययन और पूर्व शोधों की समीक्षा के बाद इन्हें भारत लौटाने की सिफारिश की।

लेख में कहा गया कि चोल ताम्रपट्टिकाएं भारत से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख हैं। इन तांबे की पट्टिकाओं में नागपट्टिनम स्थित एक बौद्ध विहार और उससे जुड़े मठों को गांवों के राजस्व और भूमि अधिकार देने संबंधी समझौते दर्ज हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, अभिलेख संख्या ओआर.1687 वाली एक वस्तु में 21 तांबे की प्लेटें हैं, जो एक कांस्य वलय से जुड़ी हुई हैं। इस वलय पर 11वीं सदी में शासन करने वाले राजेन्द्र चोल प्रथम की मुहर लगी हुई है। इनमें पांच प्लेटों पर संस्कृत और 16 प्लेटों पर तमिल भाषा में अभिलेख अंकित हैं। दूसरी वस्तु ओआर.1688 में तीन तांबे की प्लेटें हैं, जो एक अन्य कांस्य वलय से जुड़ी हैं, जिस पर कुलोत्तुंग चोल प्रथम की मुहर अंकित है। इन पर तमिल भाषा में लेख दर्ज हैं। विश्वविद्यालय ने कहा कि ये चोल ताम्रपट्टिकाएं 1862 से उसके पास सुरक्षित हैं और दक्षिण भारत में शाही चार्टर का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। ये चोल और श्रीविजय साम्राज्यों के बीच संबंधों पर भी ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती हैं। इन प्लेटों का कुल वजन लगभग 30 किलोग्राम है। इन्हें विश्वविद्यालय पुस्तकालय में शोध और शिक्षण कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता रहा है तथा प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित किया गया।

'भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे'

नई दिल्ली, 16 मई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भोजशाला की कमाल मौला मस्जिद के विवाद पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की कड़ी निंदा की। बोर्ड ने घोषणा की है कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानूनी लड़ाई में उसका हर संभव सहयोग करेगा।

- **ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा वह इस कानूनी लड़ाई में पूर्ण सहयोग देगा।**
- **बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में एतिहासिक दस्तावेजों की अनदेखी की गई है।**

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि मप्र उच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के सरकारी दस्तावेजों, गजेटियरों और मस्जिद में सदियों से जारी मुस्लिम इबादत की अनदेखी करते हुए दिया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूजा स्थलों की सुरक्षा से संबंधित कानून 1991 की भावना और संवैधानिक मूल्यों के भी प्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि फैसले में भोजशाला की कमाल मौला मस्जिद परिसर को सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों, सरकारी अभिलेखों, पुरातात्विक साक्ष्यों एवं स्वयं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएलआई) को पूर्व रुख के खिलाफ बताते हुए सख्ती से खारिज कर दिया है।

डॉ. इलियास ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पूर्व रुख स्वयं इस स्थल की साझा धार्मिक प्रकृति को स्वीकार करता रहा है। कई दशकों तक एएसआई के आधिकारिक रिकॉर्ड और साइनबोर्ड्स में इस स्थान को भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद के नाम से दर्ज किया जाता रहा, जो इसके विवादित और साझा धार्मिक स्वरूप की सरकारी मान्यता थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003 की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार के दिन पूजा की अनुमति दी गई थी जबकि मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति थी। यह व्यवस्था स्वयं इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि एएसआई दोनों समुदायों के ऐतिहासिक दावों और इबादत के अधिकारों को मान्यता देता था। इसके बावजूद, हाई कोर्ट द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करना एएसआई के पूर्व रुख से हटना है। ?

उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से यह दलील दी थी कि ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों में इस इमारत को लगातार मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि ऐसा कोई निर्विवाद ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह सिद्ध करे कि इसी स्थान पर राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर स्थित था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत ने इन प्रामाणिक ऐतिहासिक और सरकारी अभिलेखों को उचित महत्व नहीं दिया।

कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिये अब तीन भाषा व्यवस्था

नई दिल्ली, 16 मई। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9-10 के लिए तीन भाषा व्यवस्था लागू कर दी है। इनमें से दो भाषाएं अनिवार्य तौर पर भारतीय होना आवश्यक है। नई व्यवस्था इसी साल एक जुलाई से लागू होगी।

सीबीएसई की ओर से 15 मई को जारी एक परिपत्र का यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप है। यह बदलाव 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की समीक्षा के बाद किया गया है।

बोर्ड के अनुसार, विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़ नी होंगी। इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना आवश्यक है। हालांकि कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा का मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर और आंतरिक रूप से किया जाएगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का उल्लेख सीबीएसई प्रमाणपत्र में किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे को पुलिस के सुपुर्द किया

हैदराबाद, 16 मई। केंद्रीय मंत्री बंडीसंजय कुमार ने बेटे भगीरथ को पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और उनकी लीगल टीम का कहना है कि उनके बेटे को जमानत मिल जाएगी। वहीं, तेलंगाना पुलिस का कहना है कि पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी भगीरथ को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस ने भगीरथ को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था।

- **तेलंगाना पुलिस का कहना है कि मंत्री पुत्र भगीरथ, जो पॉक्सो में आरोपी है, को गिरफ्तार किया गया है यह सरेंडर नहीं था।**

अपने बेटे भगीरथ के पॉक्सो केस पर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा,''आज मैंने अपने बेटे बंदी भगीरथ को जांच के लिए एक वकील के जरिए पुलिस को सौंप दिया है।

पुलिस के मुताबिक उन्हें नारसिंगी पुलिस एकेडमी की पास से अरेस्ट किया गया। तेलंगाना केसाइबराबाद पुलिस कमिश्नर रमेश ने कहा, ''पेटबशीराबाद पॉक्सो केस के आरोपी बंडी भगीरथ को हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके से पकड़ा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। यह सरेंडर नहीं था।''

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस मामले में भगीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके एक दिन बाद बंडी संजय कुमार ने बयान में कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद बेटे से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा था।

पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ आठ मई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत 17 वर्षीय लड़की की मां ने दर्ज कराई थी।

'दुखी हूँ, मीडिया के एक वर्ग ने मेरी बात को गलत तरीके से रखा'

सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं को कॉक्रोच बताने वाली अपनी टिप्पणी पर उठे विरोध को शांत करने की कोशिश की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। ऐसा लगता है कि अपनी छवि को सुधारने के प्रयास में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को मीडिया के एक हिस्से पर शुक्रवार की उनकी कॉक्रोच वाली टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। इस टिप्पणी का भारी विरोध हुआ था।

- **उन्होंने कहा, एक मामूली से केस की सुनवाई में की गई मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि मैंने तो ''फेक डिग्री' लेकर कानूनी पेशे में घुस आए लोगों पर टिप्पणी की थी। ये लोग मीडिया, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं तो क्या आरटीआई या किसी अन्य क्षेत्र के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सब पर हमला करते हैं।**
- **ज्ञातव्य है कि एक वकील संजय दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा था, बेरोज़गार युवा कॉक्रोच जैसे होता है। इस टिप्पणी का भारी विरोध होने पर सीजेआई ने कहा, मुझे भारत के युवा पर गर्व है, यह मुझे प्रेरित करते हैं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत के युवा मेरा बहुत सम्मान करते हैं।**

सीजेआई सूर्यकांत ने एक बयान में कहा, मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने मेरे मौखिक टिप्पणियों को, जो कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान की गई थीं, गलत तरीके से पेश किया। यह बयान कानूनी समाचार वेबसाइटों में प्रकाशित हुआ।

उन्होंने कहा, ''मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने नकली और फर्जी डिग्रियों के सहारे बार (कानूनी पेशा) जैसे पेशों में प्रवेश किया। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य नेक पेशों में भी छिपकर प्रवेश कर गए हैं, इसलिए ये कीड़े-मकोड़ों (परजीवी) की तरह हैं।''

शुक्रवार को, जब उन्होंने दिल्ली के कुछ अधिवक्ताओं की संभावित फर्जी कानून डिग्रियों की जांच के लिए सीबीआई को चेतावनी दी तो उनमें से कई ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और घृणास्पद टिप्पणियां पोस्ट की थीं।

सीजेआई ने कहा था, ''समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनमें शामिल होना चाहते हैं? कुछ युवा कॉक्रोच की तरह हैं। उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और पेशे में उनकी कोई जगह नहीं है।'' वे अधिवक्ता और याचिकाकर्ता संजय दुबे को संबोधित कर रहे थे। सीजेआई ने कहा था, ''इनमें से कुछ मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में आ जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और कुछ अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शनिवार को अपने बयान, जिसमें उन्होंने अपनी छवि को सुधारने का प्रयास किया, में सीजीआई ने कहा, ''यह पूरी तरह से आधारहीन है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। न केवल मुझे हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय युवा मुझमें बहुत सम्मान और आदर रखते हैं, और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ।''

जून के मध्य...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और साथ ही, पार्टी नेतृत्व तेलंगाना जैसे राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है, जो भाजपा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर बने हुये हैं। (महिला कोटे से) डी के अरुणा जैसे नाम केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने के लिए संभावितों के रुप में चर्चा में हैं। ऐसी संभावना है कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए आप नेता राघव चड्ढा को, अगले वर्ष होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, कोई महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद दिया जा सकता है। इस बदलाव में उत्तर प्रदेश या बिहार के राज्य नेता या तो सरकार में या पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा और गठबंधन सहयोगियों के नए चेहरे, युवा सांसद और जिनका संगठनात्मक/राज्यस्तरीय रिकॉर्ड मजबूत है, उन्हें शामिल किया जाएगा। कुछ रिपोर्टों में महिलाओं को मंत्रियों के रुप में शामिल करने की संभावना भी बताई गई है, ताकि 33 प्रतिशत महिला कोटे के लक्ष्य को बढ़ावा दिया जा सके।

अदालती आदेश की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अवमानना याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने फागी उपखंड के पचाला गांव के आम रास्ते पर प्रभावशाली लोगों की ओर से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने गत 2 अप्रैल को याचिकाकर्ता को कहा था कि वह इस संबंध में जयपुर कलेक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करे और कलेक्टर उसे तीन सप्ताह में तय कर विधि सम्मत कार्रवाई करें। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता ने गत 8 अप्रैल को समस्त दस्तावेजों के साथ कलेक्टर व स्थानीय अधिकारियों को अभ्यावेदन पेश कर दिया। इसके बावजूद, कलेक्टर की ओर से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भाजपा अपनी विश्वसनीयता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्पताल परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या का शिकार बनाया गया था। मामले का विवरण सामने आने के बाद बंगाल में हंगामा मच गया था, व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी।

भाजपा के मुख्यमंत्री ने एक भीड़भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन उच्च अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय घोषित किया। उन्होंने राज्य पुलिस प्रशासन में कुछ बुनियादी सुधारों से संबंधित कई अन्य उपायों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री अधिकारी ने दोहराया कि राज्य पुलिस के अधिकारियों ने मामले को संभालने में लापरवाही की। अपने कर्तव्यों को अनुशासित अधिकारी की तरह निभाने के बजाय, उन्होंने गैर-पेशेवर तरीके से काम किया। अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि पुलिस अधिकारियों ने मृतक के माता-पिता को पैसा देने की पेशकश तक की थी।

'अगर आप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद हुआ। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लावरोव द्वारा भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति के संबंध में दी गई जानकारी की सराहना की।

'पाक तय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देगी, तो सेनाध्यक्ष ने कहा, ''अगर आपने मुझे पहले सुना है, तो मैंने कहा था... कि पाकिस्तान, अगर आतंकवादियों को आश्रय देना और भारत के खिलाफ ऑपरेशन करना जारी रखता है, तो उसे तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है, या इतिहास का।'' 'सेना संवाद' कार्यक्रम में उनकी ये टिप्पणियाँ ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के कुछ ही दिन बाद आईं। जनरल द्विवेदी की टिप्पणियाँ संक्षिप्त थीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश थीं और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराने वाली थीं।

ज्यादा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपये देने की योजना पर भी विचार कर रही थी। 5 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री सत्या कुमार यादव ने कहा कि सरकार अब तीसरे और उससे अधिक बच्चों वाले परिवारों को भी प्रोत्साहन देने का फैसला कर चुकी है।

'पंजाब में निगम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फेर किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय किसी भी राजनीतिक दल से सलाह-मशविरा किए बिना लिया गया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908